the 45th Indian Labour Conference, the Ministry of HRD has given a written assurance that it is considering the enhancement of honorarium of the mid-day meal cooks by ₹ 500 for the year 2013-14 and by ₹1,000 by 2014-15 to make it ₹ 2,000 by 2015-16. But since 2009, there has been no increase in their remuneration. Mid-day meal workers are mostly from socially-backward sections of the society and nearly 40 per cent of them are widows. So, the Government should urgently consider the matter of increasing the remuneration of mid-day meal workers.

Demand to improve train services connecting Etah in Uttar Pradesh

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, उत्तर प्रदेश का एटा जनपद प्रदेश के अत्याधिक पिछड़े जनपदों में से है। पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, एटा जिला मुख्यालय का किसी मुख्य रेल लाइन से जुड़ाव नहीं है। सन् 1964 में दिल्ली-टून्डला रेल लाइन पर स्थित छोटे से स्टेशन बरहन से एटा को जोड़ा गया था, जिस पर केवल एक पैसेन्जर रेलगाड़ी सुबह शाम आती जाती है।

एटा के नागरिकों का व्यापार, रोजगार, कृषि, शिक्षा आदि के लिए आगरा-दिल्ली-कानपुर के साथ विशेष संबंध रहता है। आगरा-दिल्ली तथा कानपुर के साथ रेल लाइन से जोड़ने हेतु एटा के हजारों नागरिकों ने अनेक बार आन्दोलन किए हैं। नागरिकों के व्यापक आन्दोलन के परिणामस्वरूप 2-3 वर्ष पूर्व रेल विभाग ने एटा से बरहन तक जाने वाली पैसेन्जर ट्रेन को आगरा तक विस्तारित कर फास्ट पैसेन्जर ट्रेन लगभग 6 माह चलाई, जिसके कारण एटा देहात, आगरा देहात के नागरिकों को काफी सुविधा महसूस हुई और रेल विभाग की आमदनी में भी काफी वृद्धि हुई। परंतु अचानक ही एटा-आगरा फास्ट पैसेन्जर को पुन: बन्द कर दिया गया, जिसके कारण एटा के नागरिकों में भारी गुस्सा है और वे पुन: आन्दोलन करने पर उतारु हैं।

अत: मैं इस अवलिम्बनीय अत्यंत लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एटा से आगरा तक सुपर फास्ट पैसेन्जर तथा एटा से कानपुर-इलाहाबाद व दिल्ली तक जाने के लिए एक-एक कोच किसी एक्सप्रेस ट्रेन से जोड़ने की कार्यवाही अविलम्ब की जाए।

Demand to include Dhangar tribe of Maharashtra in Scheduled Tribes list

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं आपका ध्यान 70 सालों से महाराष्ट्र के धनगर जनजाति पर होते आ रहे अन्याय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान द्वारा दी गई अनुसूचित जनजाति की सूची में 36 नम्बर पर होते हुए भी महाराष्ट्र की "धनगर" की जगह "धनगड" लिखे जाने की वजह से 70 सालों से धनगरों को ST (Scheduled Tribes) का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2013 से लगातार मैं इस विषय पर कार्य कर रहा हूं। भाजपा ही केवल ऐसी पार्टी रही है जो वर्ष 2013 से धनगरों का अनुसूचित जनजाति आरक्षण देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी एवं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, देवेन्द्र फडणवीस जी इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन सच बात यह भी है कि इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में धनगर समाज काफी नाराज़ है। उनके मन में यह भावना है कि उनके साथ धोखा हुआ है और जो वादा चुनावी घोषणा-पत्र में भाजपा सरकार ने किया था, जो लिखित